भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 317

5 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: यू-212 कंसोर्टियम

317. श्री डी.एम.कथीर आनन्द:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पानी और रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग से उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि और उससे संबद्ध प्रोद्योगिकी विकसित करने हेतु यू-212 कंसोर्टियम बनाने के लिए अमरीका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार ने देश में उन्नत कृषि तकनीकों को आरंभ करने के लिए अमरीका और इजराइल के साथ कोई समझौता किया है और कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसानों के किसी दल को इजराइल भी भेज रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने कृषि और इसकी संबद्ध प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यू-212 कंसोर्टियम बनाने के लिए अमरीका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फरवरी, 2023 में भारत ने कृषि जलवायु नवाचार मिशन (AIM4C) में शामिल होने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कृषि जलवायु नवाचार मिशन (कृषि जलवायु नवाचार मिशन / AIM4C) संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। कृषि जलवायु नवाचार मिशन प्रतिभागियों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को दूर करना चाहता है, ताकि जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार में निवेश और अन्य सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। साथ ही इजरायल भी अन्य देशों के बीच AIM4C का सदस्य है।

(ग): भारत और इज़राइल ने 1993 में कृषि सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत द्विपक्षीय तीन-वर्षीय कार्य योजनाओं के माध्यम से सहयोग गतिविधियों को कार्यान्वित किया जाता है। अब तक, भारत और इज़राइल के बीच 5 तीन-वर्षीय कार्य योजनाओं को औपचारिक रूप दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में 13 राज्यों में प्रचालन उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना हुई है। ये सीओई इजरायली खेती और कृषि-प्रौद्योगिकियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्यान्वित करते हुए बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अलग-अलग, समय-समय पर, विभिन्न राज्य सरकारों ने शैक्षिक और क्षमता-वर्धन गतिविधियों के हिस्से के रूप में किसान प्रतिनिधिमंडलों का इज़राइल में नेतृत्व करने की पहल की है।

*****